सौर व पवन बिजली पर है टाटा का जोर

आज का साक्षात्कार

अनिल सरदाना, एमडी व सीईओ, टाटा पावर

निजी बिजली उत्पादकों में टाटा पावर देश के अग्रणी उत्पादकों में शामिल है। कंपनी अब थर्मल के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा पर भी पूरा फोकस कर रही है। पेश हैं संवाददाता राजीव कुमार से टाटा पावर के प्रबंध निदेशक व सीईओ अनिल सरदाना की बातचीत के अंश:

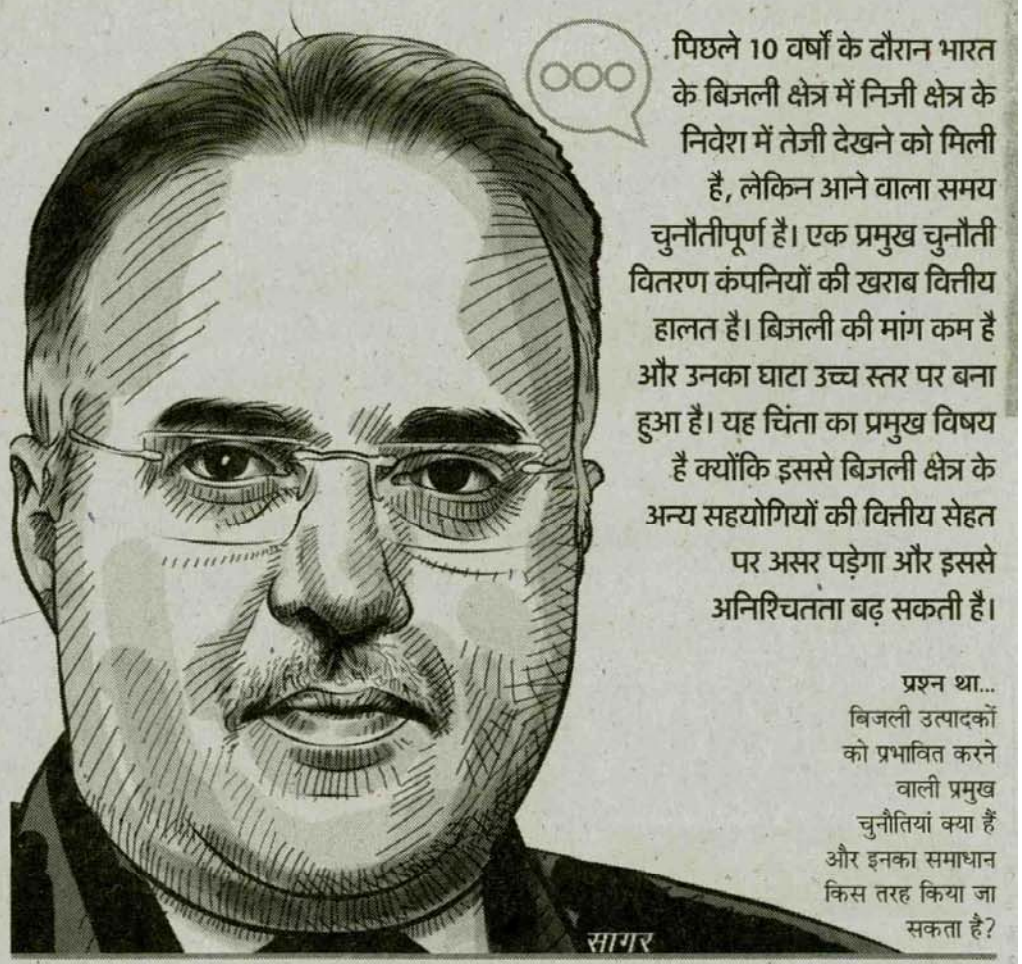

पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत के बिजली क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी देखने को मिली है, लेकिन आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। एक प्रमुख चुनौती वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय हालत है। बिजली की मांग कम है और उनका घाटा उच्च स्तर पर बना हुआ है। यह चिंता का प्रमुख विषय है क्योंकि इससे बिजली क्षेत्र के अन्य सहयोगियों की वित्तीय सेहत पर असर पड़ेगा और इससे अनिश्चितता बढ़ सकती है।

प्रश्न था...
बिजली उत्पादकों को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और इनका समाधान किस तरह किया जा सकता है?

बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की आर्थिक स्थिति एक बड़ी चिंता है। क्या हम कभी एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल (एटीएंडसी) घाटों को कम करने और वितरण प्रणाली की सेहत सुधारने में सक्षम होंगे?

एक तरफ डिस्कॉम की आर्थिक स्थिति एक बड़ी चिंता है, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में सुधार के भी अवसर हैं। बिजली क्षेत्र में बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि भारत में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत अब भी काफी कम है और डीजी (डीजल जनरेटर) सेट्स में ईंधन-तेल की खपत काफी उच्च स्तर पर है। डिस्कॉम एटीएंडसी घाटों को कम करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे वाणिज्यिक सेहत में सुधार होगा और बिजली की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि एटीएंडसी घाटों को कम करने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। देश में 56 डिस्कॉम में से 33 का एटीएंडसी घाटा 30 फीसदी से अधिक के स्तर पर बना हुआ है। बिजली मंत्रालय की उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से काफी लाभ मिला है।

क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की उदय योजना से डिस्कॉम की स्थिति में सुधार होगा?

उदय, सरकार की ओर से किया गया एक शानदार प्रयास है। हालांकि इस बात का इंतजार करना होगा कि उदय को उसी तरह से लागू किया जाए, जिस तरह से उसकी अवधारणा तैयार की गई है। इससे डिस्कॉम को अगले कुछ वर्षों में ब्रेक इवेन (घाटे से बाहर निकलना) तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। उदय का एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि राज्य, डिस्कॉम्स के पुराने और भविष्य के घाटों को ग्रेडेड तरीके से अधिग्रहीत करेंगे। पुराने बेलआउट पैकेज के विपरीत इस बार राज्य सरकारें, डिस्कॉम को होने वाले किसी भी घाटे के लिए जिम्मेदार होंगी। उदय योजना 2019 तक 'सभी के लिए बिजली' के सरकार के एजेंडे के लिए अहम भूमिका निभा सकती है।

टाटा पावर की विस्तार योजनाएं क्या हैं? इस साल के लिए आपने पूंजीगत खर्च के लिए कितना प्रावधान किया है?

कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2025 तक बिजली की कुल उत्पादन क्षमता को 20,000 मेगावाट के स्तर तक पहुंचाना है। हम इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं और वित्त वर्ष 2016-17 में हमने उत्पादन क्षमता में 1,400 मेगावाट का इजाफा किया है। कंपनी पिछले वर्षों की ही तरह करीब 1,500-2,000 करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च करना जारी रखेगी।

सरकार सौर ऊर्जा पर मुख्य रूप से ध्यान दे रही है और सरकार का लक्ष्य 2022 तक 100 गीगावाट (एक लाख मेगावाट) सोलर क्षमता की स्थापना करना है। टाटा पावर इस दिशा में क्या कर रही है?

हमने हाल ही में 2025 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के लक्ष्य को संशोधित कर 35-40 फीसदी किया है, जिसमें सौर ऊर्जा एक प्रमुख तत्व होगा। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंपनी विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी सौर एवं पवन परियोजनाएं विकसित करने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में जमीनों की भी खरीदारी कर रही है।

टाटा पावर ने पिछले वित्त वर्ष में वैलस्पन एनर्जी के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो की खरीद के साथ एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण किया था। इस सौदे के पीछे क्या प्रमुख वजह थी?

वैलस्पन के सौदे की प्रमुख वजह यह थी कि टाटा पावर की सौर ऊर्जा परिसंपत्तियां कुछ खास नहीं थीं और हमें महत्वपूर्ण आंकड़ा जुटाने में कई साल लग जाते। दूसरे, चूंकि ये परिचालन चालू हालत में थे, लिहाजा इनसे नकदी भी तत्काल प्रभाव से अर्जित होने लगी है। इस अधिग्रहण के साथ हमें अतिरिक्त भूमि भी मिली है, जिस पर अतिरिक्त सौर क्षमता को जोड़ा जा सकता है।

क्या आप मानते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा की दरों में लगातार हो रही गिरावट की वजह से अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स को ऋण जुटाने और इक्विटी फंडिंग में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?

सरकार का पूरा ध्यान अक्षय ऊर्जा क्षमताओं में इजाफा करने की ओर है, ऐसे में बड़े पैमाने पर निजी इक्विटी एक नियम बन चुका है। घरेलू प्रतिभागिता को बनाए रखने के क्रम में आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र में ऋण हासिल करने का दर्जा मिलना चाहिए। बैंकों से ऋण मुहैया कराने के अलावा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं की घोषणा की जानी चाहिए।

अब घरेलू स्तर पर कोयला आसानी से उपलब्ध है तो क्या टाटा पावर अपने किसी प्लांट के लिए आयातित कोयले की बजाय घरेलू कोयले का रुख करेगी?

यदि हम मुंद्रा पावर प्लांट की बात करें तो पिछले आदेश के मुताबिक एक शर्त यह थी कि हमें इंडोनेशिया से अनिवार्य रूप से कोयला खरीदना था। लेकिन अब ऐसी कोई शर्त लागू नहीं है और जो कुछ होना था वह हो चुका है तो हम किसी से भी कोयला खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं और हमारा मानना है कि ऐसे में हम प्रतिस्पर्धी दरों पर खरीद को प्राथमिकता देंगे।